Sector in the most backward area of the country, that is, Ladakh.

Great potentials exist for construction of big Hydel Projects both in Leh and Kargil districts of Ladakh which in the event of execution will be useful not only to the residents of Leh and Kargil districts but also to the entire state including the Armed Forces stationed in the area.

Two such projects, that is, Parkachik Hydel Project in Kargil and Damkhar Hydel Project in Leh are already in the detailed investigation stages.

I, therefore, urge upon the Government of India to take up for construction at least one Hydel Project either the Parkachik-Suru Hydel Project of Kargil or Damkhar Hydel Project of Leh in the Central Sector enabling the people living in the cold and desert area of Ladakh to have modern amenities.

(ii) Scarcity of drinking water in Ghazipur district of Uttar Pradesh

श्री जैनुल बशर(गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पेय जल का गंभीर संकट पैदा हो गया है। गाजीपुर और मुहम्मदाबाद तहसीलों में तो स्थिति भयावह हो गई है। पीने के पानी के लिए लोगों को मीलों चक्कर लगाना पड़ता है, फिर भी पानी मुश्किल से मिलता है। अधिकतर अभावग्रस्त गांव में पेय जल की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि ये गांव सन् 1972 की अभावग्रस्त सूची में शामिल नहीं थे। वास्तविकता यह है कि पिछले कई वर्षों से ये गांव पेय जल से संकट-ग्रस्त हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम ऐसे गांवों में पेय जल व्यवस्था करने में अपने को असमर्थ बताता है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार के निर्देशन के अनुसार केवल उन्हीं गांवों में पेय जल की व्यवस्था की जाती है जो 1972 की अभावग्रस्त सूची में शामिल हैं।

जहां पेय-जल योजनाएं हैं भी, वहां भी बिजली न मिलने के कारण पेय जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। जहां पेय-जल हेतु बड़े हैंड-पम्प लगाए गए हैं, वहां गांव की पूरी आबादी की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा गया है। अक्सर कई गांव ऐसे हैं जो कई भागों में दूर-दूर आबाद हैं, उनमें केवल एक भाग में हैंड-पाइप लगा दिया गया है, बहुत से हैंड-पाइप भी पानी देने में असमर्थ हो रहे हैं।

अभी मैं गाजीपुर से लौटा हूं। पेय जल के लिए वहां त्राहि-त्राहि मची हुई है। मेरा सरकार से आग्रह है कि शीघ्रातिशीघ्र गाजीपुर के अभाव ग्रस्त गांवों में पेय जल की योजना लागू की जाए। जो योजना लागू है, उनमें जैनरेटरों की व्यवस्था की जाए। गाजीपुर में पेय जल की व्यवस्था हैंड पाइपों से उपयोगी नहीं होगी, वहां तत्काल नलकूपों की योजनाएं चालू की जाएं।

(iii) Scarcity of Vanaspati in the country

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, 15 मार्च, 1984 से अप्रैल, 1984 की एक महीने की अवधि के दौरान वनस्पति के मूल्यों में लगातार वृद्धि हुई, जो इस प्रकार है :—

15 मार्च, 1984	प्रति-टिन 16½ किलोग्राम	रु० 238—250
15 अप्रैल, 1984	प्रति-टिन 16½ किलोग्राम	रु० 255—260

सरकार द्वारा वनस्पति उद्योग को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 12,000 रुपए प्रति-टन की व्यापारिक कीमत पर आयातित तेलों की 20 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा दिए जाने की व्यवस्था के बावजूद यह वृद्धि हुई है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरों में कृत्रिम अभाव दिखाकर वनस्पति की कीमतें बहुत अधिक वसूल की जा रही हैं।

दूसरी ओर वाणिज्य मंत्रालय के एक दावे के